भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/312
विवि.एसटीआर.आरईसी.231/21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषयवस्तु

अध्याय I - प्रारंभिक 4

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – 4

बी. प्रयोज्यता 4

अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ 7

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां: 7

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग 8

सी. प्रकटीकरण 9

अध्याय III – पुनर्रचना के लिए प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड 10

ए. खातों की पुनर्रचना – सामान्य अनुदेश 10

अध्याय IV - पुनर्रचना के विशेष मामले 10

ए. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना 10

बी. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान 16

अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) 17

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन 17

अध्याय VI - विशेष उपाय 21

ए. व्यापार राहत उपाय 21

अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान 22

ए. निरसन और बचाव 22

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं 23

सी. व्याख्याएँ 23

ए. पृष्ठभूमि 24

बी. संस्थागत ढांचा 24

सी. मौजूदा ऋणों की पुनर्रचना 26

डी. नए ऋण प्रदान करना 30

ई. अन्य सहायक उपाय 32

एफ. दंगे और अशांति: दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता 33

प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। ये निदेश प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए समझौता समझौतों और तकनीकी बट्टे-खाते डालना पर निर्देशों को तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण भी बनाते हैं।

कुछ ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समर्थन के बदले उधारकर्ताओं के लक्षित वर्ग के ऋण दायित्वों का त्याग / छूट शामिल है। यदि ऐसी योजनाओं की घोषणा बार-बार, असंगत रूप से, या वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की जाती है, तो इससे ऋण अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लंबे समय में, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के लिए प्रति-उत्पादक हो सकता है। क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे के मुद्दों के व्यापक निहितार्थों के अलावा, डीआरएस कुछ विवेकपूर्ण चिंताओं को भी बढ़ाता है, जिसमें बकाया राशि की प्राप्ति में देरी; ग्रामीण सहकारी बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दावों और संबंधित सरकार द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल; ग्रामीण सहकारी बैंक द्वारा नए ऋण की अनिवार्य आवश्यकता आदि शामिल हैं। ये निदेश डीआरएस में ग्रामीण सहकारी बैंक की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांतों को भी निर्धारित करते हैं और एक मॉडल संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं।इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे ।

तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 21 और 35ए के साथ पठित खंड 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इन निर्देशों को जारी करता है जो इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इन निदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक– दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू होंगे (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों ' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों का अर्थ राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक होगा, जैसाकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में परिभाषित किया गया है।

4. बैंक, राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों और / या उसके तहत बनाए गए नियमों, या अन्य वैधानिक अधिनियमों की अपेक्षाओं का पालन करेगा, यदि वे एतदद्वारा निर्धारित किए गए की तुलना में अधिक कठोर हैं।

सी. परिभाषाएं

5. इन निदेशों में, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो:

(1) *समझौता निपटान' का अर्थ उ*धारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा ।

स्पष्टीकरण: समझौता निपटान में उधारकर्ता के हिस्से पर बैंक से देय राशि का कुछ त्याग शामिल हो सकता है, जिससे उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों की उसी सीमा तक छूट हो सकती है।

(2) '*चूक*' का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई है और देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, चूक का अभिप्राय उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वीकृत सीमा से लगातार अधिक शेष राशि या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, 30 दिनों से अधिक समय तक होगा।

(3) *तकनीकी* बट्टे-खाते डालना*' उन माम*लों को संदर्भित करेगा जहां गैर-निष्पादित *आस्ति*यां उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया रहती हैं, लेकिन किसी भी ऋण के खिलाफ दावों की छूट के बिना, और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, केवल लेखा उद्देश्यों के लिए बैंकद्वारा *बट्टे-खाते डालना* (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) की जाती है।

6. अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि यहाँ परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ रखती हैं जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन या रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किए जाने वाले, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।

अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां:

7. बैंक, दबावग्रस्त आस्तियों की पुनर्रचना / पुनर्वास के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा।

8. बैंक उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी बट्टे-खाते डालने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) सभी समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक निर्धारण, अपेक्षित शर्तों के विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जैसे न्यूनतम परिपक्वन, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि;

(2) बोर्ड द्वारा तय की जानेवाली उचित सीमा और समय-सीमा के साथ ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा;

(3) उपलब्धता के अनुसार, प्रतिभूति / संपार्श्विक के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की विवेकपूर्ण गणना के बाद निपटान राशि पर पहुंचने के दौरान विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोजर के लिए अनुमेय घाटा से संबंधित प्रावधान;

(4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य पर पहुंचने के लिए कार्यप्रणाली।

(5) निम्नलिखित के अधीन समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के अनुमोदन / मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन:

(i) इस तरह की मंजूरी के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन एक प्राधिकरण (व्यक्ति या समिति, जैसा भी मामला हो) के पास होता है जो क्रेडिट / निवेश एक्सपोजर को मंजूरी देने के लिए शक्ति निहित प्राधिकरण की तुलना में पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊंचा होता है।

बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो ऋण स्वीकृत करने का हिस्सा था (व्यक्तिगत या समिति के हिस्से के रूप में) किसी भी क्षमता में उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हिस्सा नहीं होगा।

(ii) धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में समझौते के प्रस्तावों के लिए, जैसा कि पैरा 16 से 31 के संदर्भ में अनुमत है, सभी मामलों में बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

9. बैंक, ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की चूक की शीघ्र पहचान ऐसी आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके करेगा:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		**ऐसे ऋण जो परिक्रामी सुविधाओं के रूप में होते हैं जैसे कि नकद** क्रेडिट **/ओवरड्राफ्ट**	
एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णत: या आंशिक रूप से अतिदेय	**एसएमए उप-श्रेणी**	बकाया राशि, स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो - अवधि के लिए अधिक बनी रहती है
एसएमए -0	30 दिन तक	-	-
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों

			तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए - 2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

10. उधारकर्ता के खातों के एसएमए श्रेणियों में वर्गीकरण के निदेश विनियमित ईकाई के एक्सपोजर आकार पर विचार किए बिना फसल मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों के अलावा सभी ऋणों (खुदरा ऋणों सहित) के लिए लागू हैं।

11. बैंक को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2017 की सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और संहिता और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को तुरंत लागू करेगा।

सी. प्रकटीकरण

12. बैंक अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा के नोट्स' में उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- वित्तीय विवरण: प्रस्तुतियां और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय III – पुनर्रचना के लिए प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड

ए. खातों की पुनर्रचना – सामान्य अनुदेश

13. कोई भी आस्ति जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती के संबंध में ऋण के नियम और शर्तों पर पुन: परक्रामण किया गया है या पुन:निर्धारित किया गया है, उसे अव-मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पुन: परक्रामण या पुनर्निर्धारित शर्तों के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के कम से कम एक वर्ष तक ऐसी श्रेणी में रहना चाहिए।

14. किसी आस्ति का वर्गीकरण केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त पैरा 13 में निर्दिष्ट शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो।

15. जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक की है, साथ ही कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, पुनर्गठन के लिए अयोग्य रहेगा।

16. इरादतन चूककर्ता या कोई भी इकाई जिसके साथ एक इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के उपरांत पुनर्गठन के लिए पात्र होगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन) निदेश, 2025 के संदर्भ में इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक निष्पादन के अधीन है।

अध्याय IV - पुनर्रचना के विशेष मामले

ए. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना

17. समझौता निपटान का उद्देश्य बैंक के सर्वोत्तम हित में, न्यूनतम खर्च पर संकटग्रस्त उधारकर्ता से अधिकतम वसूली करना होगा।

18. समझौता निपटान उधारकर्ताओं के लिए अधिकार के मामले में उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर प्रयोग किया जाने वाला विवेक है।

19. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना भविष्य की आकस्मिक वसूली या बैंक द्वारा वसूली से संबंधित बैंक और उधारकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों के लिए पूर्वाग्रह के बिना होंगे, इस तरह के दावों के निपटान के समय या बाद में ऐसी प्राप्य की वास्तविक वसूली तक बैंक के तुलन पत्र पर किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं होने के अधीन।

बशर्ते बैंक के तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त ऐसे कोई भी दावे व्यवस्था को पुनर्रचना के रूप में माना जाएगा।

20. पैरा 19 के बावजूद, ऐसा समझौता निपटान जहां तय की गई निपटान राशि के भुगतान की अवधि तीन महीनों से अधिक हो, उन्हें पुनर्रचना माना जाएगा।

21. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान से जुड़ी कोई भी व्यवस्था पुनर्रचना की परिभाषा के अंतर्गत भी आएगी और उस पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

22. तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बैंक द्वारा की गई एक लेखा प्रक्रिया है जिसे अशोध्य ऋणों को तुलन पत्र से साफ करने के लिए किया जाता है जो या तो अप्राप्य माने जाते हैं या जिनकी वसूली में उधारदाताओं के असमान संसाधनों की खपत होने की संभावना है। हालाँकि, इस तरह के तकनीकी बट्टे-खाते डालना में उधारकर्ता के विरुद्ध दावों की कोई छूट शामिल नहीं है और इस प्रकार बैंक के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाएगा। तकनीकी बट्टे-खाते डालना से पहले की स्थिति के मुकाबले उधारकर्ताओं का कानूनी दायित्व और उनके लिए इस तरह के चूक की लागत अपरिवर्तित रहती है।

23. आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मामले में, प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण सहित अवशिष्ट एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ मूल एक्सपोजर के संदर्भ में होंगी।

बशर्ते आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि सहित प्रावधानीकरण की राशि आस्ति के सकल मूल्य पर गणना के अनुसार मौजूदा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

24. समझौता निपटान और किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी बट्टे खाते में डालने के संबंध में कम से कम तिमाही आधार पर अगले उच्च प्राधिकारी को सूचना का रिपोर्टिंग तंत्र होगा।

बशर्ते एमडी एवं सीईओ / बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।

25. बोर्ड उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:

(1) समझौता निपटान और / या तकनीकी *बट्टे-खाते डालना* (क्यू-ओ-क्यू और वाई-ओ-वाई) के अधीन खातों और राशियों की संख्या में प्रवृत्ति;

(2) उपरोक्त (1) में से, धोखाधड़ी, रेड-फ्लैग, इरादतन चूक और त्वरित अवसान खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विभाजन;

(3) राशि-वार, स्वीकृति प्राधिकारी-वार, और ऐसे खातों का व्यवसाय खंड / आस्ति-वर्गवार समूहीकरण;

(4) तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा।

26. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए नए जोखिमों को स्वीकार करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक विराम अवधि होगी।

बशर्ते कृषि ऋण एक्सपोजर के अलावा अन्य एक्सपोजर के संबंध में विराम अवधि 12 महीने की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी, जिसमें बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में उच्च विराम अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बशर्ते यह भी कि कृषि ऋण एक्सपोजर के लिए विराम अवधि बैंक द्वारा उनकी संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कृषि ऋण से भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में सूचीबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित ऋण का संदर्भ होगा।

27. तकनीकी बट्टे-खाते डालना के अधीन एक्सपोजर के संबंध में अपनाई जाने वाली विराम अवधि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी।

28. बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह के बिना इरादतन चूककर्ताओं या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे-खाते डालना कर सकता है।

29. भारतीय रिजर्व बैंक (यूसीबी / राज्य सहकारी बैंक / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 और भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- इरादतन चूककर्ताओं और बड़े

चूककर्ताओं का निष्पादन) निदेश, 2025 के संदर्भ में धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपाय, उन मामलों में लागू रहेंगे जहां कोई बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान में प्रवेश करता है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पैरा 26 और 27 में निर्दिष्ट विराम अवधि, ऐसे दंडात्मक उपायों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी।

एफएक्यू1: सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए बैंक की अनुमति देने का क्या तर्क है?

प्राथमिक विनियामक उद्देश्य किसी बैंक को बिना किसी देरी के चूक में पैसे की वसूली के लिए विभिन्न मार्गों से सक्षम करना है। समय मूल्य हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप आस्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली को बाधित करती है। समझौता निपटान को इन निदेशों के तहत एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जब धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आती है तो बैंक के लिए अनिवार्यताएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना बैंक के तुलन पत्र पर इस तरह के एक्सपोजर जारी रखने से बैंक की निधि एक अनुत्पादक आस्ति में लॉक हो जाएंगी, जो वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़े नीतिगत मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की लागत अपराधियों द्वारा वहन नहीं की जाती, तब तक सुरक्षा उपायों के अधीन, बैंक द्वारा शीघ्र वसूली एक पसंदीदा विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही या प्रारम्भ की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य के अपराधी कानूनी दंड से बच न सकें।

एफएक्यू 2: बैंक को धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खातों की पुनर्रचना करने की अनुमति नहीं है। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए एक अलग निष्पादन क्यों निर्धारित किया जाता है?

आम तौर पर पुनर्रचना में पुनर्रचना के बाद भी उधारकर्ता इकाई का निरंतर एक्सपोजर रखने वाला बैंक शामिल होता है और इसलिए, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के मामले में, बैंक को उधारकर्ता इकाई के साथ अपने क्रेडिट संबंध को जारी रखने की अनुमति देना नैतिक खतरे से भरा होगा। दूसरी ओर, एक समझौता निपटान में उधारकर्ता के साथ बैंक का पूर्ण अलगाव शामिल होता है। इसलिए, किसी बैंक को अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उधारकर्ताओं के साथ निपटान की अनुमति देने से वसूली की संभावना बढ़ जाएगी।

30. इन निदेशों के तहत उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान, प्रयोज्य किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना होंगे।

31. समझौते के लिए सिविल न्यायालयों द्वारा संचालित लोक अदालतों में संदर्भित मामलों की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये होगी।

32. उपर्युक्त पैरा 30 की किसी बैंक ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की है और वहाँ ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।

बी. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान

33. बैंक, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के संबंध में अनुलग्नक में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन

34. बैंक, मौजूदा विनियामकीय मानदंडों के अधीन, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर, सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है।

35. योजना का कोई भी प्रावधान जो उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में हो या विवेकपूर्ण कारणों से उसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उसे डीआरएस को डिजाइन करते समय परामर्श चरण के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/ प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाएं।

36. बैंक स्पष्ट रूप से उस बकाया राशि का निर्धारण करेगा जो डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी बहियों में क्रिस्टलीकृत हो सकती है, जिसमें गैर-निष्पादित खातों में संचित ब्याज भी शामिल है, ताकि सरकार वित्तीय भागीदारी की सीमा के लिए उचित रूप से व्यवस्था कर सके।

37. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाए ताकि तकनीकी आधार पर प्राधिकारियों द्वारा बाद में प्रवेश न किया जा सके।

38. योजना के नियम और शर्तों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पहलू, जिसमें नए क्रेडिट के विस्तार के लिए विराम अवधि, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि शामिल हैं, प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ प्राप्त

करने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त करते समय उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

39. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में या उसके कार्यान्वयन के बाद उपार्जित लेकिन अप्राप्त ब्याज की कोई भी छूट और / या मूलधन का त्याग, एक समझौता निपटान माना जाएगा और पैरा 17 से 32 में निहित विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

40. यदि डीआरएस के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के संपूर्ण बकाया देय राशि को कवर करती है, जिसमें बैंक द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तारीख तक अर्जित मूलधन और ब्याज शामिल है, तो इससे उधारकर्ता के ऋण दायित्वों का समापन हो जाएगा।

41. ऐसे मामलों में जहां योजना के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धन उधारकर्ता के पूरे बकाया देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट एक्सपोजर (मूलधन और / या उपार्जित ब्याज) होता है, अवशिष्ट एक्सपोजर के आस्ति वर्गीकरण का मूल्यांकन मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध के नियम और शर्तों में कोई भी परिवर्तन / आशोधन इन निदेशों में परिभाषित पुनर्रचना के परीक्षण के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

42. ऐसे उधारकर्ताओं को कोई भी नया क्रेडिट एक्सपोजर प्रासंगिक आंतरिक नीति के तहत बैंक के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा, जो मौजूदा लागू नियमों के अधीन होगा।

43. योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों को बैंक की रिपोर्टिंग इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाएगी।

44. डीआरएस के कारण सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्य राशियाँ नहीं बनायी जाएगी और बैंक द्वारा धन प्राप्त होने तक उधारकर्ता पर एक्सपोजर जारी रहेगा।

45. निधि प्राप्त होने तक, बैंक आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना जारी रखेगा और जहां भी खाते गैर-निष्पादित हैं, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वसूली उपायों के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

46. पैरा 34 से 45 में निहित निदेश 31 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगे और इन अनुदेशों में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

47. इन अनुदेशों के संदर्भ में, एक मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी राज्य सरकारों (अनुलग्नक) के साथ साझा की गई है, ताकि सरकार, ऋणदाता, उधारकर्ता आदि सहित हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी गैर-संरेखण के परिवर्जन के लिए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सके।

48. 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक समय से सरकार के पास लंबित किसी भी बकाया राशि पर 100% विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा।

49. बैंक पैरा 48 में उल्लिखित बकाया राशि के निपटान के लिए आवश्यक करेगा और संबंधित सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

अध्याय VI - विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

50. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण व्यापार व्यवधानों से ऋण के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 दिनांक 14 नवंबर, 2025 के तहत निर्दिष्ट पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय दे सकते सकते हैं। इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ, उपायों के लिए एक सावधि विधि खंड शामिल किया गया है।

अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

51. इन निदेशों के जारी होने के साथ, ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

52. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व अर्जित, उपार्जित या उसके तहत अर्जित;

(2) कोई भी दंड , जब्ती, या कोई भी सजा जो उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुई है;

(3) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या जुर्माना के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकती है जैसे कि उन निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं

53. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

54. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के प्रयोज्यता या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक को आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

अनुबंध I

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

ए. पृष्ठभूमि

1. प्राकृतिक आपदा की समय-समय पर लेकिन बार-बार होने वाली घटना से मानव जीवन पर भारी असर पड़ता है और देश के किसी न किसी हिस्से में आर्थिक गतिविधियों को व्यापक नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई तबाही के लिए सभी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर पुनर्वास प्रयास की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक पुनर्वास पर केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण कार्यक्रम तैयार करते हैं। सहकारी बैंकों को सौंपी गई विकासात्मक भूमिका प्राकृतिक आपदा की घटना से प्रभावित लोगों की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में उनके सक्रिय समर्थन की गारंटी देती है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के संदर्भ में, दो निधियों का गठन किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ)। एनडीआरएफ ढांचे में वर्तमान में बारह प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को मान्यता दी गई है, अर्थात चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और शीत लहर / पाला । कृषि मंत्रालय चार आपदाओं के लिए नोडल बिंदु है, अर्थात् सूखा, ओलावृष्टि, कीटों का हमला और शीत लहर / पाला और शेष आठ के लिए, गृह मंत्रालय आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए समय-समय पर संप्रभु (केंद्र / राज्य सरकार) द्वारा राहत के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को इनपुट सब्सिडी और वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।

3. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के सदस्य के रूप में बैंक उधारकर्ताओं की उभरती आवश्यकता के अनुसार मौजूदा ऋणों का पुनर्व्यवस्थित करने और नए ऋणों को मंजूरी देने के माध्यम से राहत उपाय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक को एक समान और ठोस कार्रवाई तेजी से करने में सक्षम बनाने के लिए, ये दिशानिर्देश चार पहलुओं को कवर करते हुए जारी किए गए हैं यथा संस्थागत ढांचा, मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, नए ऋण प्रदान करना और अन्य सहायक राहत उपाय।

बी. संस्थागत ढांचा

4. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नीति / प्रक्रियाओं की स्थापना

(1) प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र, घटना का समय और तीव्रता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए यह अनिवार्य है कि किसी बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्रवाई की एक योजना हो ताकि आवश्यक राहत और सहायता अत्यंत तेजी से और बिना समय की बर्बादी के प्रदान की जा सके। इसके अलावा, बैंकों और पीएसीएस की सभी शाखाएं इन स्थायी अनुदेशों से परिचित होंगी। जिला / राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित घोषणा लागू करने के बाद स्थायी अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। यह अपेक्षित है कि ये अनुदेश राज्य सरकार के अधिकारियों और सभी जिला कलेक्टरों को भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी संबंधित लोग प्रभावित क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूक हों।

5. डीसीसीबी को विवेकाधीन शक्तियां

(1) जिला परामर्शदात्री समिति / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा तय की गई कार्रवाई के संबंध में सहकारी समितियों / एसटीसीबी के रजिस्ट्रार से नए अनुमोदन की अपेक्षा के परिवर्जन के लिए डीसीसीबी को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जा सकती हैं। कुछ क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों के अलावा जहां इस तरह की विवेकाधीन शक्तियां महत्वपूर्ण हैं, वित्त के पैमाने को अपनाना, ऋणों का आवश्यकता आधारित पुनर्गठन, ऋण अवधि का विस्तार, मार्जिन, सुरक्षा, उधारकर्ता की पुरानी ऋण से उत्पन्न कुल देनदारी को ध्यान में रखते हुए नए ऋण की स्वीकृति जहां प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप वित्तपोषित संपत्ति क्षतिग्रस्त या खो गई थी और ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण / मरम्मत के लिए वित्तपोषित नया ऋण।

6. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक

(1) प्राकृतिक आपदा की घटना में जो किसी राज्य के बड़े हिस्से को कवर करती है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक बैंक तत्काल एक विशेष बैठक बुलाएगा। समिति, राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से राहत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना विकसित करेगी। यदि आपदा ने राज्य के केवल एक छोटे से हिस्से / कुछ जिलों को प्रभावित किया है, तो प्रभावित जिले (जिलों) की जिला परामर्शदात्री समिति के संयोजक को तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए। विशेष एसएलबीसी / डीसीसी बैठक में, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जा सकता है ताकि त्वरित राहत उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

(2) जिन क्षेत्रों में आपदा गंभीर है, वहां राहत उपायों की समीक्षा समय-समय पर विशेष रूप से गठित टास्क फोर्स / उप-समिति द्वारा साप्ताहिक / पाक्षिक बैठकों के माध्यम से की जाएगी जैसा कि एसएलबीसी / डीसीसी द्वारा तय किया गया है।

7. **दायरा**

(1) ये दिशानिर्देश उन किसानों / ऋण लेने वालों पर लागू होंगे जो राज्य सरकार / प्राधिकरणों द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं और इन दिशानिर्देशों के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

8. प्राकृतिक आपदा की घोषणा

(1) यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा की घोषणा केंद्र / राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि प्राकृतिक आपदा की घोषणा और घोषणाओं / प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए कोई एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इन घोषणाओं / प्रमाणपत्रों को विभिन्न राज्यों में अन्नेवारी, पिसवारी, गिरदावरी आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। फिर भी, कृषि ऋणों के लिए राहत उपाय बढ़ाने के लिए सामान्य सूत्र, जिसमें बैंक द्वारा ऋणों का पुनर्निर्धारण शामिल है, यह है कि फसल के नुकसान का आकलन 33% या उससे अधिक होना चाहिए। इस नुकसान का आकलन करने के लिए, जबकि कुछ राज्य फसल की उपज में नुकसान का निर्धारण करने के लिए फसल कटाई का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अन्य लोग आंखों से देखकर अनुमान लगाने / दृश्य इंप्रेशन पर भरोसा कर रहे हैं।

(2) अत्यधिक बाढ़ जैसी स्थितियों में, जब यह काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और / या भूमि और अन्य संपत्तियों को व्यापक क्षति हुई है, तो ऐसे मामले पर राज्य सरकार / जिला प्राधिकरणों द्वारा विशेष रूप से बुलाई गई एसएलबीसी / डीसीसी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा जहां संबंधित सरकारी पदाधिकारी / जिला कलेक्टर फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से 'अनेवारी' (फसल नुकसान का प्रतिशत - चाहे जो भी नाम दिया गया हो) का अनुमान नहीं लगाने के कारणों को समझाएंगे और प्रभावित आबादी के लिए राहत प्रदान करने का निर्णय आंखों से देखकर अनुमान लगाने / दृश्य इंप्रेशन के आधार पर लेने की आवश्यकता है।

(3) हालाँकि, दोनों ही मामलों में, एसएलबीसी / डीसीसी इन घोषणाओं पर कार्रवाई करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक है।

सी. मौजूदा ऋणों की पुनर्रचना

9. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, लोगों की आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने और आर्थिक संपत्ति के नुकसान के कारण उनकी पुनर्भुगतान क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसलिए, मौजूदा ऋण की पुनर्रचना द्वारा ऋण चुकौती में राहत आवश्यक हो सकती है।

10. कृषि ऋण: अल्पकालिक उत्पादन ऋण (फसल ऋण)

(1) प्राकृतिक आपदा की घटना के समय अतिदेय ऋणों को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्रचना के लिए पात्र होंगे। प्राकृतिक आपदा की घटना के वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय अल्पकालिक ऋण की मूल राशि के साथ-साथ ब्याज को सावधि ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) पुनर्रचित ऋण की चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता, आर्थिक आस्तियों के नुकसान और इससे होने वाले संकट के प्रभाव के आधार पर भिन्न हो सकती है। यदि नुकसान 33% और 50% के बीच है तो अधिकतम दो वर्ष की चुकौती अवधि (एक वर्ष अधिस्थगन अवधि सहित) की अनुमति दी जाएगी। यदि फसल का नुकसान 50% या उससे अधिक है, तो पुनर्भुगतान अवधि को अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित)।

(3) सभी पुनर्रचित ऋण खातों में, कम से कम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जाएगा। कोई बैंक ऐसे पुनर्रचित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा पर जोर नहीं दे सकता है।

11. कृषि ऋण: दीर्घकालिक (निवेश) क्रेडिट

(1) मौजूदा सावधि ऋण किस्तों को उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

(i) प्राकृतिक आपदा में जहां केवल उस वर्ष की फसल क्षतिग्रस्त होती है और उत्पादक संपत्ति को नुकसान नहीं होता है, तो बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त का पुन: निर्धारण करेगा और ऋण अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाएगा। इस व्यवस्था के तहत पहले के वर्षों में इरादतन डिफ़ॉल्ट की गई किस्तें पुनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगी। बैंक को उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का भुगतान भी स्थगित करना पड़ सकता है।

(ii) प्राकृतिक आपदा में जहां उत्पादक आस्तियां आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उधारकर्ताओं को नए ऋण की आवश्यकता होती है, ऋण अवधि के विस्तार के माध्यम से पुनर्निर्धारण उधारकर्ता की कुल देनदारी (पुराना सावधि ऋण, पुनर्रचित फसल ऋण, यदि कोई हो और दिया जा रहा नया फसल / सावधि ऋण) के मुकाबले समग्र पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सब्सिडी, बीमा योजनाओं आदि के तहत उपलब्ध मुआवजा। जबकि पुनर्रचित / नए सावधि ऋण के लिए कुल चुकौती अवधि आधार-से-मामले के आधार पर भिन्न हो सकती है, आम तौर पर यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. अन्य ऋण

(1) आपदा की गंभीरता के आधार पर, एसएलबीसी / डीसीसी इस बात पर विचार करेगा कि क्या अन्य सभी ऋणों (अर्थात कृषि ऋणों के अलावा) जैसे संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण, ग्रामीण कारीगरों, व्यापारियों, सूक्ष्म / लघु औद्योगिक इकाइयों या चरम स्थितियों के मामले में ऋणों का सामान्य पुनर्निर्धारण आवश्यक है। मध्यम उद्यम। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो सभी ऋणों की वसूली निर्दिष्ट अवधि तक स्थगित कर दी जाती है, तो एक बैंक प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की आवश्यकता का आकलन कर सकता है और उसके खाते की प्रकृति, पुनर्भुगतान क्षमता और नए ऋणों की आवश्यकता के आधार पर, प्रत्येक बैंक द्वारा उचित निर्णय लिए जाएंगे।

(2) किसी भी इकाई को उसके पुनर्वास के लिए ऋण देने का प्राथमिक विचार बैंक द्वारा आकलित उद्यम की व्यवहार्यता पर आधारित होगा।

13. आस्ति वर्गीकरण

(1) पुनर्रचित ऋणों के आस्ति वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार होगी:

(i) अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्रचित हिस्से को वर्तमान बकाया के रूप में माना जा सकता है और उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इन सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। तथापि, बैंक को समय-समय पर निर्धारित किए गए ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिमों के लिए अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत ऐसे पुनर्रचित खातों से ब्याज आय को निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

(ii) शेष बकाया के लिए आस्ति वर्गीकरण, जो पुनर्गठित हिस्से का हिस्सा नहीं है, इसके अनुमोदन **के** मूल नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, उधारकर्ता से प्राप्त राशि को उधार देने वाले बैंक द्वारा विभिन्न आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों जैसे मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, को 'मानक आस्ति' माना जाएगा और इसके भविष्य के आस्ति वर्गीकरण को इसकी स्वीकृति के नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा।

(iv) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई बैंक प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने में सक्रिय है, प्राकृतिक आपदा की तारीख पर पुनर्गठित खातों के आस्ति वर्गीकरण का लाभ तभी उपलब्ध

होगा जब प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पुनर्रचना पूरी हो जाएगी। अत्यधिक आपदा की स्थिति में, जब एसएलबीसी / डीसीसी का विचार है कि शाखाओं के लिए सभी प्रभावित ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के लिए यह अवधि पर्याप्त नहीं होगी, तो वह विस्तारित अवधि मांगने के कारणों को देते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से संपर्क करेगा। इन अनुरोधों पर प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(v) प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति के कारण दूसरी बार या अधिक पुनर्रचना किए गए खातों को पुनर्गठन पर समान संपत्ति वर्गीकरण श्रेणी बनाए रखनी चाहिए। तदनुसार, एक पुनर्रचित मानक संपत्ति का प्राकृतिक आपदा के कारण बाद में की गई पुनर्रचना को दूसरी पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा, अर्थात, मानक आस्ति वर्गीकरण को बनाए रखा जाएगा। तथापि, अन्य सभी पुनर्रचना मानदंड लागू होंगे।

14. बीमा आय का उपयोग

(1) जबकि ऋणों के पुनर्निर्धारण से संबंधित उपरोक्त उपायों का उद्देश्य किसानों को राहत प्रदान करना है, बीमा आय को आदर्श रूप से नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने खरीफ 2016 से प्रभावी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की मौजूदा योजनाओं को प्रतिस्थापित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए सभी मौसमी कृषि कार्यों (एसएओ) ऋणों को निर्दिष्ट उदाहरणों में फसल चक्र के सभी चरणों सहित फसल कटाई के बाद के जोखिमों के लिए अनिवार्य रूप से बीमा कवर प्रदान किया जाना है (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश)। बीमाकृत फसलों के कवरेज, कटौती किए गए प्रीमियम आदि के मूल्यांकन की सुविधा के लिए किसानों का विवरण फसल बीमा के लिए एकीकृत पोर्टल में बैंक द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक है जो http://www.agriinsurance.gov.in/ पर उपलब्ध है।

(2) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्रचना के दौरान बैंक, बीमा कंपनी से प्राप्त बीमा आय को भी ध्यान में रखेगा। बीमा आय को उन मामलों में 'पुनर्रचित खातों' में समायोजित किया जाएगा जहां उधारकर्ता को नया ऋण दिया गया है। तथापि, बैंक सहानुभूति के साथ कार्य करेगा और

उन मामलों में बीमा दावा प्राप्त होने की उचित निश्चितता होने पर पुनर्रचना करने और नए ऋण देने के लिए प्रतीक्षा किए बिना विचार करेगा जहां दावा प्राप्त होने की उचित निश्चितता है।

डी. नए ऋण प्रदान करना

15. नए ऋणों का अनुमोदन

(1) एक बार एसएलबीसी / डीसीसी द्वारा अल्पकालिक ऋणों के रूपांतरण के लिए लंबित होने पर ऋणों की पुनर्रचना करने का निर्णय लेने के बाद, बैंक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फसल के वित्त के पैमाने और खेती क्षेत्र के आधार पर प्रभावित किसानों को नया फसल ऋण प्रदान करेगा।

(2) कृषि और संबद्ध गतिविधियों (कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि) में बैंक सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है, जो विभिन्न उद्देश्यों जैसे मौजूदा आर्थिक संपत्ति (संपत्तियों) की मरम्मत और / या नई संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक ऋण के लिए हो सकती है। इसी प्रकार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों, सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों आदि को अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए नए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। बैंक प्रभावित उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों की आवश्यकता का आकलन करेगा और अन्य बातों के अलावा, ऋण की आवश्यकता और नए ऋणों की स्वीकृति के लिए उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऋणों की मात्रा पर निर्णय लेगा।

(3) बैंक मौजूदा उधारकर्ताओं को बिना किसी संपार्श्विक के 10,000 रुपये तक का उपभोग ऋण भी प्रदान करेगा। हालाँकि, बैंक के विवेक पर सीमा को 10,000/- रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

16. नियम और शर्तें

(1) गारंटी, प्रतिभूति और मार्जिन

(i) केवल व्यक्तिगत गारंटी के अभाव में ऋण से वंचित नहीं किया जाएगा। जहां बाढ़ से क्षति या विनाश के कारण बैंक की मौजूदा प्रतिभूति कम हो गई है, वहां अतिरिक्त नई प्रतिभूति की कमी के लिए सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। नया ऋण दिया जाएगा, भले ही प्रतिभूति का मूल्य (मौजूदा के साथ-साथ नए ऋण से प्राप्त की जाने वाली संपत्ति) ऋण राशि से कम हो। नए ऋणों के लिए, बैंक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा।

(ii) जहां फसल ऋण (जिसे सावधि ऋण में परिवर्तित किया गया है) पहले फसल की व्यक्तिगत प्रतिभूति / बंधक पर स्वीकृत किया गया था और उधारकर्ता परिवर्तित ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में भूमि का प्रभार / बंधक की प्रस्तुति करने में सक्षम नहीं है, तो उसे केवल भूमि को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थता के आधार पर रूपांतरण सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि उधारकर्ता ने पहले से ही भूमि पर बंधक / प्रभार पर सावधि ऋण लिया है, तो बैंक परिवर्तित सावधि ऋण के लिए दूसरे प्रभार से संतुष्ट होगा। बैंक रूपांतरण सुविधा प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष की गारंटी पर जोर नहीं देगा।

(iii) जहां भूमि को प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है, मूल टाइटल रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र उन किसानों को वित्तपोषण के लिए स्वीकार किया जाएगा जिन्होंने अपने टाइटल का प्रमाण खो दिया है जैसे कि पंजीकृत शेयर-क्रॉपर्स को जारी टाइटल विलेख या पंजीकरण प्रमाण पत्र। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जहां भूमि समुदाय के स्वामित्व में है, सामुदायिक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

(iv) मार्जिन आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान / सब्सिडी को मार्जिन के रूप में माना जाएगा।

17. ब्याज की दर

(1) इस मामले में ब्याज की दर मौजूदा निदेशों के अनुसार होगी। हालाँकि, अपने विवेकाधिकार के क्षेत्रों के भीतर, बैंक उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक देखेगा और आपदा प्रभावित लोगों को रियायतपूर्ण व्यवहार करेगा। वर्तमान देय राशि में चूक के संबंध में, कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंक ब्याज प्रभार के चक्रवृद्धि को भी उचित रूप से स्थगित करेगा। कोई बैंक कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाएगा और परिवर्तित / पुनर्निर्धारित ऋणों के संबंध में पहले से ही लगाए गए दंडात्मक ब्याज को माफ करने पर विचार करेगा। प्राकृतिक आपदा की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, एसएलबीसी / डीसीसी ब्याज दर रियायत पर विचार करेगा जिसे उधारकर्ताओं को दी जा सकती है ताकि राहत प्रदान करने में बैंकों के बीच दृष्टिकोण में एकरूपता हो।

(2) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने के अनुसार (अल्पकालिक फसल ऋणों पर आईएस योजना में शामिल होने के अधीन), अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्रचित ऋण

राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंक को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के पुनर्रचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दरें लागू होंगी।

ई. अन्य सहायक उपाय

18. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर छूट

(1) यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि किसी बड़ी आपदा से विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कई व्यक्तियों के पास अपनी पहचान और व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में बैंक अधिकारी के सामने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के साथ फोटो के आधार पर एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोला जाएगा। उपरोक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होगा जहां खाते में शेष राशि 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है या दी गई राहत की राशि (यदि अधिक है) और खाते में कुल जमा राशि 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है या एक वर्ष में दी गई राहत की राशि (यदि अधिक है)।

19. बैंकिंग सेवा तक पहुंच प्रदान करना

(1) बैंक रिज़र्व बैंक / नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की परामर्श के तहत अस्थायी परिसरों से अपनी प्राकृतिक आपदा प्रभावित शाखाओं का संचालन कर सकता है। 30 दिनों से अधिक समय तक अस्थायी परिसर को जारी रखने के लिए, बैंक उचित अधिकारियों से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। बैंक, रिजर्व बैंक / नाबार्ड को सूचना देकर प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट कार्यालयों, विस्तार काउंटरों या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं आदि की स्थापना भी कर सकता है।

(2) प्रभावित लोगों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एटीएम को बहाल करने पर उचित महत्व दिया जा सकता है या ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी।

(3) प्रभावित लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए बैंक अपने विवेक अन्य उपाय कर सकते हैं जैसे: एटीएम फीस माफ करना, एटीएम निकासी सीमा बढ़ाना; ओवरड्राफ्ट / समय पर जमा / क्रेडिट कार्ड / अन्य ऋण किस्त भुगतान आदि पर शीघ्र निकासी दंड के लिए फीस माफ करना और क्रेडिट कार्ड धारकों को अपनी बकाया राशि को 1-2 वर्षों में चुकाने योग्य ईएमआई में बदलने का विकल्प देना। इसके अलावा, नियमित ब्याज के अलावा कृषि ऋण खाते में डेबिट किए गए सभी प्रभारों को प्रभावित लोगों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए माफ किया जा सकता है।

एफ. दंगे और अशांति: दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

20. जब भी रिज़र्व बैंक / नाबार्ड, बैंक को दंगा / उपद्रव प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने की सलाह देता है, तो उक्त दिशानिर्देशों का पालन बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य प्रशासन द्वारा दंगों / उपद्रवों से प्रभावित होने के रूप में पहचाना गया है, दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाए। बड़े पैमाने पर दंगों की स्थिति में जहां राज्य / क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा प्रभावित है और राज्य प्रशासन दंगा / अशांति से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने की स्थिति में नहीं है और एसएलबीसी के विशिष्ट निर्णय के अधीन, 'वास्तविक व्यक्तियों' की पहचान करने का दायित्व बैंक पर होगा।

21. राज्य सरकार से अनुरोध / सूचना प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा किसी बैंक को सलाह जारी करना और उसके बाद बैंक द्वारा अपनी शाखाओं को अनुदेश जारी करने के परिणामस्वरूप आम तौर पर दंगा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में देरी होती है। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि दंगा / अशांति की घटना होने पर, जिला कलेक्टर, यदि आवश्यक हो तो डीसीसी की बैठक बुलाने के लिए लीड बैंक अधिकारी से कह सकते हैं और दंगा / अशांति से प्रभावित क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को जितना नुकसान हुआ है उसकी डीसीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि डीसीसी संतुष्ट है कि दंगा / अशांति के कारण जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है, तो उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार राहत दंगा / अशांति से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे मामलों में जहां कोई जिला परामर्शदात्री समितियां नहीं हैं, जिला कलेक्टर राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक से बैठक आयोजित करने के लिए अनुरोध कर सकते है और बैठक का हिस्सा होगा। बैठक की कार्यवाही की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी।

अनुबंध II

मॉडल परिचालन प्रक्रिया

कवरेज और अर्थ

1. मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) के प्रयोजन के लिए, ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिनमें उधारकर्ताओं के लक्षित खंड के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए वित्तीय अधिकारियों द्वारा वित्त पोषण शामिल है जिसे विनियमित संस्थाओं को त्याग / छूट देने की आवश्यकता होती है।

2. ऐसी किसी भी डीआरएस की घोषणा / अधिसूचना में इस प्रकार के समर्थन की घोषणा करने की आवश्यकता वाली विशिष्ट तनाव या संकट की स्थिति शामिल होनी चाहिए। क्रेडिट संस्कृति के लिए इस तरह के डीआरएस के व्यापक निहितार्थ को देखते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में स्पष्ट राजकोषीय समर्थन के माध्यम से व्यापक आधार वाले राहत उपायों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है जब वित्तीय तनाव को कम करने के अन्य उपाय विफल हो गए हों और डीआरएस को केवल अंतिम उपाय के रूप में माना गया हो ।

अधिसूचना-पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए समन्वित कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ जुड़ सकती हैं। इन योजनाओं में उधारकर्ताओं की

पहचान, प्रभाव का आकलन, कार्यान्वयन समय-सीमा, उधारदाताओं को सरकार द्वारा देय राशि के निपटान से संबंधित मुद्दों का समाधान आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

4. डिजाइन विशेषताओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीआरएस क्षेत्र / राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करे या उधारकर्ता सेगमेंट में नैतिक संकट उत्पन्न न हो। क्रेडिट निपटान पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना का वित्तपोषण

5. आवश्यक निपटान राशि को पूरी तरह से कवर करने के लिए किसी भी प्रस्तावित डीआरएस के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान / निधियन अग्रिम रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहां विनियमित संस्थाओं की सरकार के पास बकाया राशि है जो कि पहले की डीआरएस योजनाओं से संबंधित है तो नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णता: पूर्व-वित्त पोषित आधार पर की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस केवल प्रभावित उधारकर्ताओं पर लक्षित होना चाहिए और इसमें समय पर पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंधात्मक वचन-पत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इसमें वस्तुनिष्ठ आधार पर पात्र उधारकर्ताओं का निर्धारण करने के लिए मानदंड, सरकार की ओर से धन के निपटान में देरी के क्षतिपूर्ति खंडों के साथ-साथ दावा दाखिल करने / जमा करने की कट-ऑफ तिथियों सहित गंभीर/महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समय-सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

7. डीआरएस को सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं से धन प्राप्त करने की तारीख तक मूलधन और संचित ब्याज सहित कवर किए जा रहे उधारकर्ताओं की पूरी बकाया राशि शामिल करना चाहिए ।

8. डीआरएस को विनियमित इकाई की बहियों में सरकार से प्राप्य राशि के सृजन आवश्यकता नहीं **है** । विनियमित संस्थाओं का उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर जारी रहेगा और सरकार से प्राप्त निधि की सीमा तक कम हो जाएगा।

9. योजना का संपूर्ण कार्यान्वयन और विनियमित संस्थाओं के प्रति सरकारों द्वारा दावों का निपटान आम तौर पर 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

10. डीआरएस में रिज़र्व बैंक **/** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किसी भी विनियामक निदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

11. डीआरएस के डिजाइन में कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व डालता है जिसमें सम्मिलित है :

ए. उधारकर्ता से अपने देय राशि की/का आंशिक या संपूर्ण छूट / त्याग;

बी. उन उधारकर्ताओं को नया ऋण प्रदान करें जिनका ऋण माफ 1कर दिया गया है;

सी. भविष्य में बजटीय समर्थन की प्रत्याशा में कोई प्रतिबद्धता न करें;

डी. उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए, सरकार से धन की प्राप्ति लंबित होने पर, उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का अनुसरण करना बंद करें।

तथापि, यदि विनियमित संस्थाएं डीआरएस के डिजाइन के दौरान या उसके बाद में, अपने बोर्ड की अनुमोदित नीतियों के अनुसार उपरोक्त में से किसी पर सहमत होती हैं, तो वह लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगा।